अफ्रीकी संघ

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (11 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फत्तह अल-सीसी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष बन गये हैं।
- यह पद प्रत्येक वर्ष अफ्रीका महाद्वीप के पाँच क्षेत्रों में बदलता रहता है अर्थात् प्रत्येक वर्ष एक नए अफ्रीकी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को यह पद दिया जाता है।

क्या है?

- अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसके सदस्य अफ्रीका के सभी 55 देश होते हैं। लेकिन इसमें अफ्रीका में स्थित यूरोपीय प्रभुता वाले विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित नहीं होते हैं।
- अफ्रीकी संघ सबसे पहले इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में 26 मई, 2001 को स्थापित हुआ था और अगले वर्ष 9 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में इसका अनावरण किया गया था।
- अफ्रीकी संघ अफ्रीकी एकता संघ को विस्थापित कर बना था। 32 अफ्रीकी सरकारों ने मिलकर 25 मई, 1963 को यह संगठन अदीस अबाबा में शुरू किया था।
- अफ्रीकी संघ के अधिकांश बड़े निर्णय इसकी महासभा में लिए जाते हैं जो हर छह महीने पर बैठती है।
- इस महासभा में सभी देशों और सरकारों के प्रमुख सदस्य होते हैं।
- अफ्रीकी संघ का सचिवालय अदीस अबाबा में स्थित है।

उद्देश्य

- अफ्रीकी देशों और अफ्रीकियों के मध्य एकता एवं एकजुटता को बढ़ावा देना।
- सदस्य देशों की सम्प्रभुता, भौगोलिक एकता और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- उन उपायों में तेजी लाना, जिनसे महाद्वीप की राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक एकात्मक्ता संभव हो सके।

पांडुलिपि केंद्र की स्थापना

इंडियन एक्सप्रेस, (11 Feb.)

संदर्भ

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मैथिली भाषा अथवा मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए दरभंगा में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी।
- पूर्व में इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री से इसके लिए एक कमेटी गठित करने की मांग की थी, जिस पर मंत्री ने मैथिली विद्वानों के नाम का सुझाव देने के लिए कहा था।

क्या की गयी घोषणा?

- मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए दरभंगा में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी।
- यह केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या कामेश्वर सह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में से किसी एक परिसर में स्थापित होगा।
- मिथिलाक्षर का उपयोग आसान हो, इसके लिए लिपि को भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के द्वारा जल्द से

जल्द कम्प्यूटर की भाषा (यूनिकोड) में परिवर्तित करने का काम पूरा किया जाएगा।
- साथ ही मिथिलाक्षर लिपि को सीखने के लिए ऑडियो-विजुअल तकनीक भी विकसित की जाएगी।

समिति और उसके सुझाव
- चार सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में अतिप्राचीन लिपि को बचाने के लिए कई सुझाव दिए हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने अधिकांश सुझावों पर अपनी सहमति देते हुए जल्द से जल्द उन पर काम करने का आश्वासन दिया था।
- इस बैठक में मिथिला और मैथिली के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था।

ईरानी इस्लामी क्रांति

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (11 Feb.)

संदर्भ
- वर्ष 2019 में ईरान इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगाँठ मना रहा है।

क्या है?
- ईरानी इस्लामी क्रांति उन घटनाओं की श्रृंखला को कहते हैं, जो 1979 में गठित हुई थीं और जिनके फलस्वरूप अंतत: ईरान के राजा मुहम्मद रेजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा था।
- जिसके बाद उनकी सरकार के स्थान पर एक इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख ग्रैंड अयोतुल्लाह रुहोल्लाह खोमैनी बने जो उस समय के विद्रोही गुटों में से एक के नेता थे।
- इस आन्दोलन में इस्लामी संगठनों के अतिरिक्त बहुत सारे वामपंथी और छात्र गुट भी शामिल थे।

कारण
- पश्चिमी धर्म-निरपेक्ष नीतियों के अंतर्गत कथित रूप से हो रहे अत्याचारों का प्रतिरोध करना।
- अमेरिका द्वारा समर्थित राजतंत्र का नाश करना।

परिणाम
- इस्लामी क्रांति के कारण राजतंत्र समाप्त हो गया और ईरान एक धर्मतांत्रिक देश बन गया।
- विश्व-भर में कई तख्तापलट हुए हैं, जिनके पीछे राष्ट्रवाद अथवा समाजवाद की भावनाएँ रही हैं। लेकिन ईरानी क्रांति में ऐसा पहली बार हुआ है कि धर्म के नाम पर नया तंत्र स्थापित किया गया।

आउटरीच कार्यक्रम

Pib, द हिन्दू, (12 Feb.)

संदर्भ
- हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए 'आउटरीच' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हितधारकों को समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी।
- इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़ी वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया।
- विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
- इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी। 39 जिलों को वस्त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था। 39 जिलों में 12 हैंडलूम, 19 हस्तशिल्प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे।

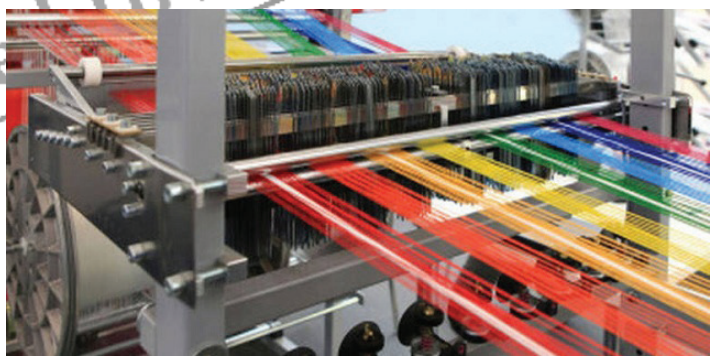

क्या है आउटरीच कार्यक्रम?
- आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे- स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई-धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण

किट का वितरण, कारीगरों तथा बुनकरों के लिए पहचान-पत्र का पंजीयन व वितरण, 24×7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

- इसमें 9 तथा 10 फरवरी, 2019 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इसके बाद 11 और 12 फरवरी को राज्य स्तर पर हैंडलूम, हस्तशिल्प और पावरलूम उत्पादों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम से लाभ

- एमएसएमई क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच तथा समर्थन व सहयोग से इकाईयों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्त्र क्षेत्र विकसित होगा।
- आउटरीच कार्यक्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे टेक्सटाइल हब की एमएमएफ वस्त्र निर्माण इकाईयों को लाभ मिलेगा।
- एक घंटे से कम समय में ऋण स्वीकृति से सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के समय की बचत होगी।
- निरीक्षक द्वारा जांच को समाप्त करने, निरीक्षक के जांच को कम्प्यूटर द्वारा चयनित करने, पोर्टल पर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अपलोड करने आदि कदमों से उद्यमियों को व्यापार करने में आसानी होगी।
- भारत के कुल वस्त्र उद्योग में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है।
- नई पहलों से अधिकांश इकाईयों को फायदा मिलेगा। जैसे- नए ऋणों के लिए ब्याज दर में दो प्रतिशत की कटौती, निर्यात क्रेडिट के लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती, 59 मिनटों के अंदर 1 करोड़ रूपये तक की ऋण-स्वीकृति आदि।

आशय पत्रक (एसओआई) पर हस्ताक्षर

Pib, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, (12 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में नीति आयोग तथा माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन (एमएसडीएफ) ने प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने और दस्तावेजों को संहिताबद्ध करने के लिए आशय पत्रक (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ऐसा एमएसडीएफ के भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ किए गए कार्य के सामूहिक अनुभव के आधार पर किया गया है।

मुख्य तथ्य

- इस नवीनतम भागीदारी के तहत नीति आयोग और सुसान डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गए उन सुधारों का दस्तावेजीकरण करेगा, जिनसे शिक्षा में प्रणालीगत सुधारों की शुरूआत हुई है और पिछले वर्षों के दौरान इन सुधारों से शिक्षा परिणामों में सुधार आना शुरू हुआ है।
- समझौते के तहत राज्य के नेताओं, सलाहकारों, अनुसंधान एजेंसियों और शिक्षकों को शामिल करके एक संयुक्त दल राज्यों से शिक्षा पर आधारित परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित करने में मिलकर कार्य करेगा।

- शिक्षा में प्रणालीगत सुधार के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। एक स्तर पर शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए समन्वित और सतत् प्रयासों के साथ-साथ शैक्षिक तथा प्रशासन दोनों सुधारों की जरूरत है।

नीति आयोग के बारे में

- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- 1 जनवरी, 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया।

- यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
- नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा।

पर्सनल लॉ (संशोधन) बिल-2018

इकोनॉमिक टाइम्स, (13 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में राज्यसभा में पर्सनल लॉ (संशोधन) बिल- 2018 पारित हुआ, जिसके अनुसार अब कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकेगा।
- आखिरी दिन राज्यसभा में इस विधेयक पर सहमति बनने के बाद इसे बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया।
- 10 अगस्त, 2018 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे लोकसभा से 7 जनवरी, 2019 को पारित किया गया और 13 फरवरी, 2019 को राज्य सभा से पारित किया गया।

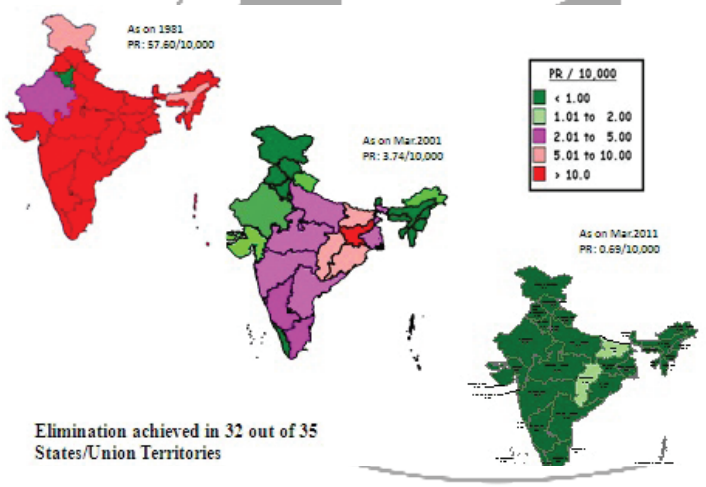

आवश्यकता क्यों पड़ी?

- वर्तमान में कुष्ठ रोग पूर्णत: निदान योग्य है लेकिन कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेद करने वाले पुराने विधायी उपबंध विभिन्न विधियों में आज भी विद्यमान हैं।
- ऐसे में इन विभेदकारी उपबंधों को समाप्त करने के लिये विधेयक लाया गया है।

पृष्ठभूमि

- पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 में 5 पर्सनल कानूनों में तलाक के लिए दिए गए आधार से कुष्ठ रोग को हटाने का प्रावधान है।
- इन पांच पर्सनल कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 शामिल हैं।
- विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन कानूनों और प्रावधानों को खारिज करने की सिफारिश की थी, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।
- इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के उस घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का आह्वान किया गया है।
- वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कदम उठाने को कहा था।

अंतर्राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन

टाइम्स ऑफ इंडिया, (13 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल के रूप में पांचवां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया।
- संस्थागत मजबूती के तौर पर विश्व बैंक की सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP, ड्रिप) चलाई जा रही है।

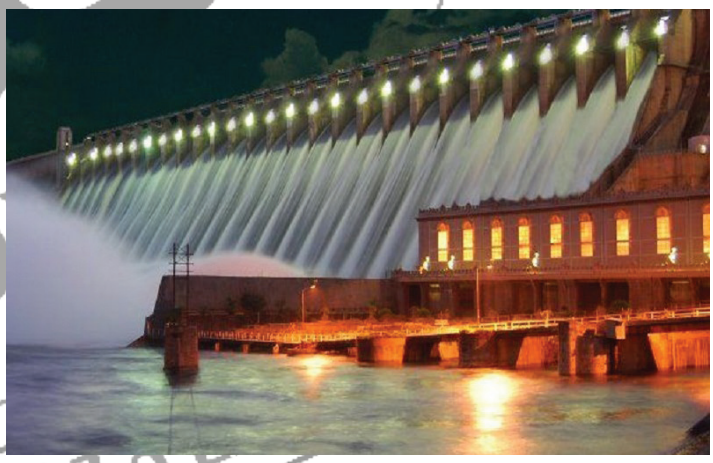

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना क्या है?

- ड्रिप एक छह वर्षीय परियोजना है, जिसे भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित कर रहा है।
- इस परियोजना का समन्वयन और पर्यवेक्षण केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय बाँध सुरक्षा संगठन के द्वारा हो रहा है। इसके लिए यह संगठन एक परामर्शी प्रतिष्ठान की सहायता ले रहा है।

लक्ष्य

- इसे भारत में विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
- शुरू में यह परियोजना केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 223 बाँधों के लिए थी, परन्तु बाद में इसमें कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड भी शामिल कर लिए गए, जिससे बाँधों की योग संख्या 250 हो गयी।

- इसका मुख्य उद्देश्य – चुनिन्दा बांधों की सुरक्षा और सक्षमता में सुधार, भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा से सम्बंधित संस्थागत निर्माण को मजबूत बनाना है।
- सात ड्रिप राज्य हैं- झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

भारत-फिनलैंड समझौता

Pib, (13 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इस एमओयू पर जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

प्रभाव

- हस्ताक्षरित एमओयू के तहत पृथ्वी के सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) से जुड़ी संभावनाओं की तलाश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- फिनलैंड की सरकार के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि का विकास संभव हो पाएगा।

कौन-कौन से क्षेत्रों को होगा लाभ

- पृथ्वी का सुदूर संवेदन।
- उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन।
- अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह संबंधी अन्वेषण।
- अंतरिक्ष उपकरणों (ऑब्जेक्ट) और जमीन आधारित प्रणाली का विकास, परीक्षण एवं परिचालन।
- भारत के प्रक्षेपण यानों द्वारा फिनलैंड के अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपित करना।
- अंतरिक्ष से जुड़े डेटा की प्रोसेसिंग एवं उपयोग करना।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग पर आधारित अभिनव अनुप्रयोगों और समाधानों (सॉल्यूशन) को विकसित करना।
- उभरते नये अंतरिक्ष अवसरों और डेटा पारिस्थितिकी एवं बाह्य अंतरिक्ष के सतत् उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करना।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फत्तह अल-सीसी को 2 वर्ष के लिए अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया।
2. अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, जिसके सदस्य सभी अफ्रीकी देश हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'पांडुलिपि केन्द्र की स्थापना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मैथिली भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए दरभंगा में पांडुलिपि केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
2. यह केन्द्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. 'ईरानी इस्लामी क्रांति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 2019 में ईरान इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है।
2. इस आन्दोलन में इस्लामी संगठनों के अतिरिक्त बहुत सारे वामपंथी और छात्र गुट भी शामिल थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. 'आउटरीच कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।
2. वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आशय पत्रक पर हस्ताक्षर नीति आयोग और माइकल तथा सुसान डेल फाउंडेशन ने प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से किया।
2. 1 जनवरी, 2015 में नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. हाल ही पारित में पर्सनल लॉ (संशोधन) बिल, 2018 के तहत किस रोग के आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकेगा?

(a) कुष्ठ रोग (b) टी.वी. रोग
(c) पार्किंसन (d) माइग्रेन

7. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया?

(a) ओडिशा (b) नई दिल्ली
(c) गुजरात (d) तमिलनाडु

8. भारत-फिन लैण्ड समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए इन देशों के बीच समझौता हुआ है।
2. इस समझौते में फिनलैण्ड द्वारा भारत को पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए तकनीकि सहायता प्रदान करने की बात की गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

नोट : 9-10 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(a), 4(d), 5(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence